



## संसद टीवी विशेष: डजिटल भुगतान क्रांति

### प्रलम्ब के लिये:

[यूनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस \(UPI\)](#), [डजिटल लेन-देन](#), [समावेशी विकास](#), [डजिटल भुगतान](#), [भारत इंटरफेस फॉर मनी \(BHIM\)](#), [UPI 123PAY](#), [जन धन बैंक खाते नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया \(NPCI\)](#), [गुड्स एंड सर्विसिज़ टैक्स \(GST\)](#), [डजिटल वॉलेट](#), [पेटीएम](#), [प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण \(DBT\) योजनाएँ](#), [भारतीय रज़िर्व बैंक \(RBI\)](#), [इंटरनेट ऑफ थिंग्स \(IOT\)](#), [भुगतान और नपिटान प्रणाली \(PSS\) अधिनियम 2007](#), [बुनियादी ढाँचा](#), [राजकोषीय घाटा](#), [वदेशी भंडार](#), [UPI \(यूनफाइड भुगतान इंटरफेस\)](#) ।

### मेन्स के लिये:

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये डजिटल भुगतान का महत्त्व और चुनौतियाँ ।

### चर्चा में क्यों

हाल ही में [यूनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस \(UPI\)](#) की अभूतपूर्व सफलता के साथ भारत में डजिटल लेन-देन में आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई है ।

- वर्ष 2023 के वित्तीय वर्ष के दौरान संपूर्ण भारत में **100 बिलियन से अधिक डजिटल लेन-देन** हुए ।

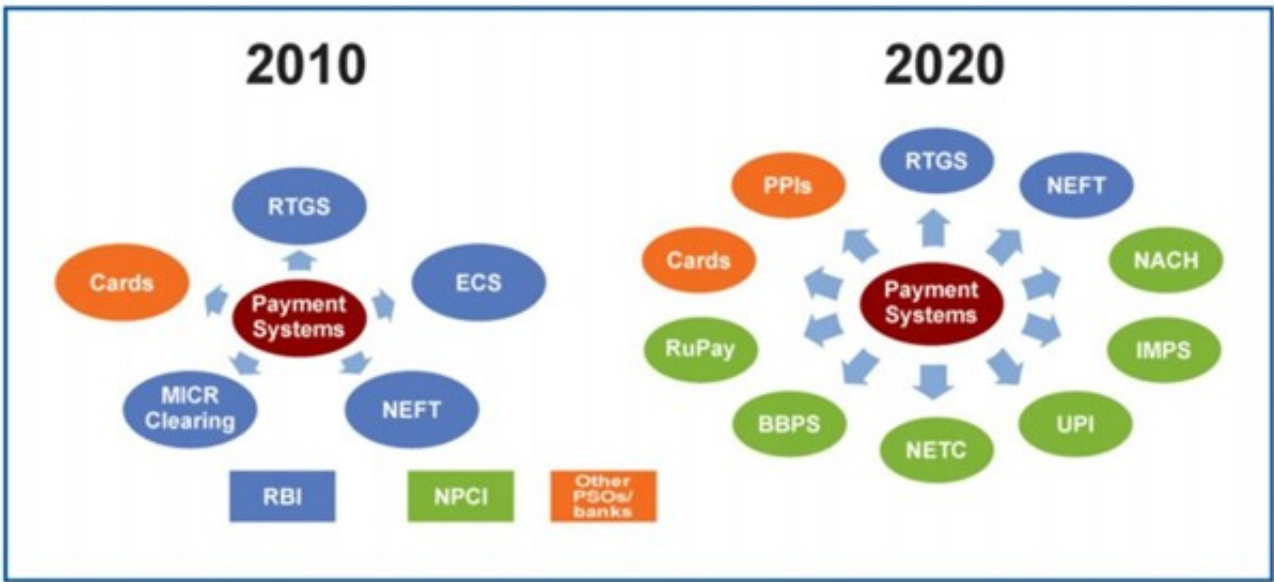
### मुख्य बढि क्या है?

- भारत में विश्व के सभी [डजिटल पेमेंट्स](#) का **46%** हिस्सा है, वर्तमान में भारत में सभी डजिटल भुगतानों में यूपीआई लेन-देन का हिस्सा **80%** है ।
- वर्ष 2012-13 में **162 करोड़ डजिटल पेमेंट** हुए थे, जबकि वर्ष 2023-24 में फरवरी माह तक यह संख्या 14,726 करोड़ हो गई है ।
- वर्ष 2022 में तत्काल डजिटल लेन-देन का मूल्य संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के संयुक्त लेन-देन से चार गुना अधिक था ।

### (डजिटल पेमेंट)

डजिटल भुगतान प्रणाली, जैसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के रूप में भी जाना जाता है, **मोबाइल फोन, POS टर्मिनल या कंप्यूटर** जैसे डजिटल उपकरणों के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में धन के हस्तांतरण को संदर्भित करता है ।

- वभिन्न प्रकार के डजिटल भुगतान मोड में शामिल हैं:
- [UPI \(यूनफाइड पेमेंट इंटरफेस\)](#)
- [भारत इंटरफेस फॉर मनी \(BHIM\)](#)
- [UPI 123PAY](#)
- [UPI लाइट](#)
- [कार्ड्स \(उदाहरण, रूपे डेबिट कार्ड\)](#)
- [तत्काल भुगतान सेवाएँ \(IMPS\)](#)
- [आधार सक्षम भुगतान प्रणाली \(AePS\)](#)



## डजिटल पेमेंट्स के घटक:

### ■ JAM ट्रान्जिटी:

- **जन धन खाते:** 46 करोड़ से अधिक **जन धन बैंक खाते** खोले गए हैं, जिनमें महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है।
- **आधार:** लगभग सभी वयस्कों के पास बायोमेट्रिक पहचान संख्या है और **1.3 बिलियन से अधिक पहचान-पत्र जारी** किये गए हैं।
- **मोबाइल:** वर्ष 2016 के बाद से डेटा लागत में उल्लेखनीय गिरावट के कारण मोबाइल फोन की पहुँच बढ़ गई है।

### ■ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI):

- **नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)** द्वारा वर्ष 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ लॉन्च किया गया, UPI एक सार्वजनिक-नज्दी साझेदारी है जो बैंक खातों से जुड़े सीधे भुगतान के लिये एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।
- **तत्काल भुगतान सेवा (IMPS)** UPI का एक उन्नत संस्करण है, जो कई बैंकिंग सुविधाओं, नरिबाध फंड रूटिंग और व्यापारी भुगतानों को मिलाकर एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भाग लेने वाले बैंक के) में कई बैंक खातों का प्रबंधन करता है।

## NPCI का परिचय:

- **नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)** एक गैर-लाभकारी कंपनी है, जो भारत में खुदरा भुगतान और नपिटान प्रणाली संचालित करने के लिये **भारतीय रजिस्ट्रार बैंक (RBI)** तथा **इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA)** द्वारा की गई एक पहल है।
- इस संगठन की स्थापना वर्ष 2008 में **भुगतान और नपिटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007** के तहत की गई थी।
- **NPCI इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (NIPL):** NIPL वदेशों में UPI और रूपे जैसी घरेलू भुगतान प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने तथा अन्य देशों के साथ भुगतान प्रौद्योगिकियों का सह-निर्माण करने के लिये NPCI की सहायक कंपनी है।

# NPCI'S SYSTEMS

- National Financial Switch (ATMs)
- National Automated Clearing House (NACH)
- CTS Cheque Clearing
- Immediate Payment Systems (IMPS)
- RuPay Card
- Aadhaar Enabled Payment System (AEPS)
- Bharat Bill Payment System (BBPS)
- Unified Payments Interface (UPI)



Payment Ecosystem

Consumer - Who initiates the transactions.

Merchants- Who accept the transactions.

Acquirers-The bank of Merchants.

Issuers -The bank for consumers.

Linking all of these is Networks like Visa, Mastercard, etc.

## डजिटल भुगतान का महत्त्व:

- **सुविधाओं में वृद्धि:** डजिटल भुगतान ने व्यक्तियों के लिये दैनिक जीवन को अधिक सुविधाजनक बना दिया है।
- **वित्तीय समावेशन:** इसने उन लाखों भारतीयों तक क्रेडिट और बचत सहित बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच का वस्तुतः कया है, जिनके पास पहले से बैंक सुविधा नहीं थी।
- **अंतिम मील तक पहुँच:** डजिटल भुगतान ने व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सरकारी कार्यक्रमों और कर संग्रह की पहुँच बढ़ा दी है।
- **उद्यमिता को प्रोत्साहन:** [डजिटल अवसंरचना](#) नवाचार के लिये एक आधार के रूप में कार्य करता है, जिससे उद्यमियों को कम लागत पर नवाचार करने की सुविधा मिलती है।
- **व्यवहारिक बदलाव:** अधिक-से-अधिक लोग नकदी-संचालित अर्थव्यवस्था से डजिटल लेन-देन की ओर संक्रमण कर रहे हैं जो लोगों के व्यवहार में आए महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है।
- **नकदी पर निर्भरता में कमी:** नकदी रहित अर्थव्यवस्था को अपनाने से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है और अवैध धन के संचरण की रोकथाम होती

है।

- **संवर्द्धति कर आय:** डिजिटल लेन-देन में वृद्धि से आय की अधिक कुशल ट्रेकिंग की सुविधा मिलती है और कर संग्रह प्रयासों को बढ़ावा मिलता है।

## भारत में डिजिटल भुगतान के संबंध में क्या पहल की गई हैं?

- **यूनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI):** UPI की शुरुआत से स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए विभिन्न बैंक खातों के बीच धन का त्वरित और नरिबाध अंतरण संभव हुआ है जिससे भारत के डिजिटल भुगतान परविश में क्रांति आई है।
- **RuPay कार्ड:** यह कार्ड NPCI द्वारा देशज रूप से विकसित भुगतान नेटवर्क है, जो अन्य अंतरराष्ट्रीय कार्ड का घरेलू विकल्प प्रदान करता है।
  - इसका उद्देश्य भुगतान का कफायती समाधान प्रदान कर डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
- **GST नेटवर्क (GSTN):** यह करदाताओं को अपने **माल और सेवा कर (GST)** रिटर्न दाखल करने तथा कर का भुगतान ऑनलाइन करने के लिये एक एकीकृत मंच प्रदान कर डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- **डिजिटल वॉलेट सेवाओं का उदय:** **Paytm, PhonePe और Google Pay** जैसी **डिजिटल वॉलेट** सेवाओं ने भारत में अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की है, जो उपयोगकर्ताओं को धन का डिजिटल संग्रहण करने तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की एक वस्तुतः शृंखला के लिये भुगतान करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करती है।
- **सरकारी सहायकी और लाभ: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं,** जहाँ सरकारी सहायकी और कल्याणकारी भुगतान का अंतरण प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जाता है, ने लोगों को बैंक खाते खोलने तथा डिजिटल भुगतान वधियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया है।
- **सहायक नयामक परविश:** **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** और अन्य नयामक नकियों द्वारा किये नयामक सुधार तथा प्रदत्त प्रोत्साहनों से डिजिटल भुगतान की संवर्द्धि, सुरक्षा, अंतरसंचालनीयता एवं उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु अनुकूल ढाँचा स्थापित हुआ है।

## भारत में डिजिटल भुगतान से संबंधित क्या चुनौतियाँ हैं?

- **डिजिटल अवसंरचना:** महत्त्वपूर्ण सुधारों के बावजूद, **नरिबाध इंटरनेट कनेक्टिविटी और वदियुत तक पहुँच** के संबंध में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, **असमानता** बनी हुई है, जिससे डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में बाधा का सामना करना पड़ रहा है।
- **डिजिटल साक्षरता:** देश के एक बड़े हिस्से में बुनियादी **डिजिटल साक्षरता कौशल** का अभाव है, जिससे डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से उपयोग करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** डिजिटल लेन-देन में वृद्धि के साथ, **डेटा उल्लंघन, पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी** जैसे साइबर सुरक्षा खतरे अधिक प्रचलित हुए हैं, जो व्यक्तियों तथा व्यवसायों के लिये जोखिम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।
- **गोपनीयता संबंधी मुद्दे:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल सेवाओं के प्रसार के साथ व्यापक मात्रा में उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र होती है जिससे डिजिटल क्षेत्र में **वैयक्तिक डेटा की गोपनीयता** तथा **सुरक्षा** के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **समुदायों के बीच डिजिटल अंतराल:** डिजिटल अवसंरचना, शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक असमान पहुँच शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच डिजिटल अंतराल को बढ़ाती है।

## आगे की राह

- **RBI का भुगतान वज़िर्न 2025:** डिजिटल भुगतान परदृश्य के लिये **5I-** अखंडता (Integrity), समावेशन (Inclusion), नवाचार (Innovation), संस्थागतकरण (Institutionalization) और अंतरराष्ट्रीयकरण (Internationalization) पर बल देना डिजिटल भुगतान पारितंत्र को आकार देने के लिये आवश्यक है।
- **धोखाधड़ी के संबंध में जागरूक करने के लिये डिजिटल साक्षरता में सुधार:** डिजिटल शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल लेनदेन के दौरान होने वाली संभावित धोखाधड़ी से अवगत कराना है।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग: इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)** आधारित भुगतान प्रणालियों के लिये एक ढाँचा विकसित करने की आवश्यकता है, जो ग्राहकों को स्मार्टफोन और टैबलेट से इतर कनेक्टेड डिवाइसों के माध्यम से लेन-देन करने में सक्षम बनाता है।
- **भुगतान के लिये कानूनी और संस्थागत अवसंरचना की समीक्षा:** RBI **संदाय और नपिटान प्रणाली (PSS) अधिनियम 2007** को भारत के विकसित डिजिटल भुगतान परदृश्य के साथ संरेखित करने के लिये इसकी व्यापक समीक्षा शुरू कर रहा है।
- **नवाचार और नयामक शक्ति को बढ़ावा देना:** नए **डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण वधियक, 2022** और **डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023** जैसी वधियाँ पहलों का प्रभाव घरेलू तथा वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान में विकास को प्रोत्साहित करने एवं अत्याधुनिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिये तैयार है।



# भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली

डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का अर्थ है डिजिटल डिवाइस या चैनल (बैंक ट्रांसफर, मोबाइल मनी, क्यूआर कोड आदि) का उपयोग करके एक भुगतान खाते से दूसरे भुगतान खाते में धन स्थानांतरित करना।



## NPCI द्वारा भुगतान प्रणाली

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) खुदरा भुगतान हेतु एक व्यापक इकाई है (भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007)।

### तत्काल भुगतान सेवा (IMPS)

- ⊕ खुदरा ग्राहकों के लिये
- ⊕ सीमा- ₹1-5 लाख (शुल्क+जीएसटी)
- ⊕ 24/7(तत्काल निपटान)
- ⊕ प्रदाता: बैंक, पीपीआई, मोबाइल वॉलेट कंपनियाँ

### एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)

- ⊕ IMPS आधारित डिजिटल भुगतान ऐप के लिये प्रौद्योगिकी
- ⊕ पुश एवं पुल हस्तांतरण
- ⊕ फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर जैसे अन्य देशों द्वारा भी अपनाया गया
- ⊕ UPI-Lite+NFC: ऑफलाइन भुगतान के लिये
- ⊕ BHIM-UPI: धन हस्तांतरण ऐप

### रुपे कार्ड पेमेंट गेटवे (RuPay)

- ⊕ 3 चैनलों में काम करता है: - एटीएम, प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस, ऑनलाइन पोर्टल
- ⊕ PMJDY के साथ निशुल्क दिया जाता है
- ⊕ विदेशों में भी अपनाया गया (जैसे मॉरीशस)

### विभिन्न पहलें

- ⊕ भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) और यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम (UPMS)
- ⊕ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC)
- ⊕ PAI चैटबॉट (एआई आधारित व्हेरी रिज़ॉल्यूशन)
- ⊕ भारत QR
- ⊕ ई-रूपी (e-RUPI)
- ⊕ आधार पेमेंट ब्रिज (APB) प्रणाली
- ⊕ आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS)

## RBI की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (CPS)

### रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS)

- ⊕ उच्च मूल्य के हस्तांतरण हेतु
- ⊕ निम्न सीमा: ₹2 लाख (कोई ऊपरी सीमा नहीं) (कोई शुल्क नहीं)
- ⊕ 24/7 (तत्काल निपटान)
- ⊕ बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा उपलब्ध

### लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (LPSS)

- ⊕ NEFT/RTGS के लिये RBI का आपातकालीन विकल्प
- ⊕ अस्थायी, पोर्टेबल समाधान

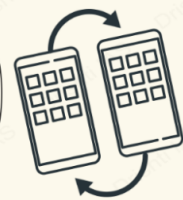


### नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT)

- ⊕ मध्यम-श्रेणी के हस्तांतरण हेतु
- ⊕ RBI द्वारा कोई सीमा नहीं (कोई शुल्क नहीं)
- ⊕ 24/7 (30 मिनट के अंतराल पर बैंकों के बीच सकल राशि का निपटान)
- ⊕ बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा उपलब्ध

### डिजिटल भुगतान नियामक निकाय/सूचकांक

- ⊕ डिजिटल हस्तांतरण लोकपाल
- ⊕ भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS)



## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में दिखने वाले 'डजिलॉकर' के संबंध में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. यह डजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक डजिटल लॉकर ससिस्टम है
2. यह आपके ई-दस्तावेजों तक आपकी पहुँच को संभव बनाता है चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

**??????:**

प्रश्न. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेंस को सरकार का अवभाज्य अंग बनाने में पहल की है"। वविचना कीजिये। (2020)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sansadtv-vishesh-digital-payment-revolution>

